of them were fishermen who had completed their sentence and were awaiting their repatriation to Pakistan. One of them was taken into custody by BSF on 15.10.1997 for illegally crossing the border. Their involvement in espionage has not come to notice.

In this regard, eight police personnel, who were on duty, at the time of escape, have been placed under suspension and an enquiry into the incident is in progress.

Following the incident, the strength of the guards at JIC Bhuj has been increased. It is not correct that Kutch area is the centre of Pakistani smugglers.

The cases of smuggling etc. are registered with the local police under various provisions of law and therefore, details in this regard are maintained by the state government.

बलात्कार के मामले

4657. **श्री अखिलेश दास:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान (अब तक) देश में सभी राज्यों में युवतियों-महिलाओं के साथ बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हुए बलात्कार के कितने मामले पुलिस थानों में दर्ज किए गए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछेक मामलों में युवतियां-महिलाएं गर्भवती हुई है; और

(घ) क्या कुछेक मामलों को पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं तथा शहरी क्षेत्रों में बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान देश में हुई बलात्कार की घटनाओं के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। **(नीचे देखिए)**

(ख) और (ग) इस संबंध में विशिष्ट सूचना, तुरंत सुलभ नहीं है। अपराध की अलग-अलग घटनाओं के ब्यौरे भी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल पता लगाना तथा रोकथाम करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामले में उठाए जाने वाले निवारक और दण्डात्मक उपायों के बारे में समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार संगत कानूनों को और अधिक कठोर तथा दण्डात्मक बनाने के उद्देश्य से उनमें आशोधन एवं संशोधन भी करती रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1997	1998	टिप्पणी =(1998 के आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	906	152	मार्च
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	11	मार्च
3.	असम	645	225	अप्रैल
4.	बिहार	189	NAउ०न०	उ०न०
5.	गोवा	15	7	मई

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	296	64	मार्च
7.	हरियाणा	341	110	अप्रैल
8.	हिमाचल प्रदेश	131	29	अप्रैल
9.	जम्मू व कश्मीर	163	24	मार्च
10.	कर्नाटक	245	67	अप्रैल
11.	केरल	571	178	अप्रैल
12.	मध्य प्रदेश	3411	1161	अप्रैल
13.	महाराष्ट्र	1206	449	अप्रैल
14.	मणिपुर	8	4	मई
15.	मेघालय	26	NAउ०न०	उ०न०
16.	मिजोरम	49	17	अप्रैल
17.	नागालैंड	15	6	मई
18.	उड़ीसा	558	NAउ०न०	उ०न०
19.	पंजाब	175	61	अप्रैल
20.	राजस्थान	255	391	अप्रैल
21.	सिक्किम	7	3	मई
22.	तमिलनाडु	287	55	मार्च
23.	त्रिपुरा	98	30	मई
24.	उत्तर प्रदेश	1390	209	फरवरी
25.	पश्चिम बंगाल	824	176	मार्च
	कुल (राज्य)	13858	3429	मार्च
26.	अ० और नि० द्वीप समूह	9	1	मई
27.	चंडीगढ़	9	3	अप्रैल
28.	दादरा और नगर हवेली	1	3	अप्रैल
29.	दमन और द्वीव	1	0	फरवरी
30.	दिल्ली	458	136	मई
31.	लक्षद्वीप	0	0	मई
32.	पांडेचेरी	5	0	अप्रैल
	कुल (संघ शासित)	483	143	
	कुल (समस्त भारत)	14341	3572	

स्रोतः मासिक अपराध आंकड़े।
आंकड़े अस्थायी हैं।
नोटः 1997 के उड़ीसा के आंकड़े नवम्बर माह तक हैं।
उ०न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं है।